

ग्लोबल साउथ और भारत : 2030 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के अवसर

संदीप बिड़ला

सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान
प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन, म.प्र.

सुदीप बिड़ला

सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान
प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धार, म.प्र.

सार

यह शोध पत्र ग्लोबल साउथ या दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South Cooperation - SSC) की अवधारणा, उसके विकास और सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals - SDGs) की प्राप्ति में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका का विश्लेषण करता है। भूमंडलीकरण और वैश्विक चुनौतियों के इस दौर में, पारंपरिक उत्तर-दक्षिण सहायता मॉडल के पूरक के रूप में दक्षिण-दक्षिण सहयोग एक सशक्त और प्रभावी तंत्र के रूप में उभरा है। यह विकासशील देशों के बीच अनुभवों, ज्ञान, प्रौद्योगिकी और संसाधनों के आदान-प्रदान पर केंद्रित है, जिससे साझा विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है। विशेष रूप से, यह पत्र भारत की भूमिका और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दक्षिण-दक्षिण सहयोग के माध्यम से उपलब्ध अवसरों पर प्रकाश डालता है। इसका उद्देश्य यह दर्शाना है कि कैसे दक्षिणी देश मिलकर गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और असमानता जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, जिससे 2030 एजेंडा को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके।

शब्द कुंजी : ग्लोबल साउथ, साउथ साउथ कोऑपरेशन, दक्षिण दक्षिण सहयोग, ssc, ब्रिक्स, भूमंडलीकरण, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, एमडीजी, MDG, सतत विकास लक्ष्य, एसडीजी 2030, sdg, उत्तर दक्षिण सहयोग, un south south, undp, ट्राइएंगुलर साउथ कोऑपरेशन, TSC, nam, ibsa, ila, isa, बाडूंग सम्मेलन, जी77, bapa, ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन, नैरोबी घोषणा, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, इंटरनेशनल सोलर एलायंस, जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना।

Received 02 Sep., 2026; Revised 10 Sep., 2026; Accepted 12 Sep., 2026 © The author(s) 2026.
Published with open access at www.questjournals.org

प्रस्तावना

वैश्विक विकास परिदृश्य में, दक्षिण-दक्षिण सहयोग (SSC) एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरा है, जो विकासशील देशों को उनके साझा अनुभवों, ज्ञान और संसाधनों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। पारंपरिक उत्तर-दक्षिण सहायता मॉडल के विपरीत, SSC समानता, आपसी सम्मान और गैर-हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर आधारित है, जो इसे विकासशील देशों की विशिष्ट आवश्यकताओं और संदर्भों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ, एसडीजी को प्राप्त करने की चुनौती जटिल और बहुआयामी हो गई है, जिसमें गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य जैसी व्यापक समस्याओं का समाधान शामिल है। ऐसे में, दक्षिण के देश एक-दूसरे से सीखकर और मिलकर काम करके इन चुनौतियों से निपटने के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करते हैं।

उत्तर-दक्षिण सहयोग:

यह विकसित देशों (उत्तर) और विकासशील देशों (दक्षिण) के बीच होने वाला एक पारंपरिक सहयोग है। इसमें विकसित देश, जैसे अमेरिका और यूरोपीय देश, विकासशील देशों को आर्थिक सहायता, तकनीकी ज्ञान और मानवीय सहायता प्रदान करते हैं। यह सहयोग अक्सर एकतरफा होता है, जहाँ देने वाला और लेने वाला स्पष्ट रूप से अलग होते हैं।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग:

यह विकासशील देशों (दक्षिण) के बीच आपसी सहयोग को दर्शाता है। इसमें ये देश एक-दूसरे के साथ ज्ञान, संसाधन और विशेषज्ञता साझा करते हैं। यह सहयोग किसी बाहरी शक्ति पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। उदाहरण के लिए, भारत का किसी अफ्रीकी देश को तकनीकी प्रशिक्षण देना या दोनों देशों का मिलकर किसी परियोजना पर काम करना। यह एक-दूसरे की समान चुनौतियों को समझने और सामूहिक रूप से उनका समाधान निकालने पर आधारित है।

यह शोध पत्र ग्लोबल साउथ और दक्षिण-दक्षिण सहयोग की अवधारणा, उसके ऐतिहासिक विकास, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उसकी प्रासंगिकता और विशेष रूप से भारत जैसे देशों के लिए उपलब्ध अवसरों को समझने का प्रयास करता है।

साहित्य की समीक्षा:

दक्षिण-दक्षिण सहयोग (SSC) पर साहित्य का एक समृद्ध भंडार मौजूद है, जो इसकी अवधारणा, विकास और महत्व पर विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। हम उपलब्ध प्रमुख साहित्य स्रोतों का संक्षिप्त अवलोकन करेंगे:

* "Reclaiming the politics of South-South cooperation: Globalizations" (Bhan, M., 2017) (tandfonline.com): यह लेख दक्षिण-दक्षिण सहयोग की राजनीतिक प्रकृति और उसके विकास के कालक्रम पर विशेष प्रकाश डालता है। भान (2017) तर्क देते हैं कि SSC केवल आर्थिक या तकनीकी आदान-प्रदान नहीं है, बल्कि यह उपनिवेशवाद विरोधी युग में शुरू हुई एक राजनीतिक परियोजना है जिसका उद्देश्य वैश्विक शक्ति की गतिशीलता को चुनौती देना और एक अधिक न्यायसंगत विश्व व्यवस्था का निर्माण करना है। एक "वि-औपनिवेशिक ग्लोबल साउथ परिप्रेक्ष्य" से, भान 1945 के बाद SSC के तीन अलग-अलग अवधियों की पहचान करते हैं: 1. "कॉन्सर्टेशन (Concertation) (1945–1981)" - जहां दक्षिणी देश एकजुट हुए

और एक सामूहिक आवाज उठाई; 2. "कंटेनमेंट (Containment) (1981–1995)" - जहां नव-उदारवादी नीतियों और उत्तर-दक्षिण सहायता के वर्चस्व के कारण SSC को हाशिए पर धकेल दिया गया; और 3. "कॉप्टेशन बनाम कंफ्रंटेशन (Cooptation vs Confrontation) (1995–वर्तमान)" - जहां SSC को वैश्विक विकास ढांचे में सह-opt करने की कोशिश की गई, लेकिन साथ ही दक्षिणी देशों ने वैश्विक प्रशासन में अधिक प्रभावी भागीदारी के लिए टकराव भी किया। यह लेख SSC को नव-उदारवादी वैश्वीकरण के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है, जो विकासशील देशों के बीच एकजुटता और सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। यह इस बात पर जोर देता है कि SSC का विकास शीत युद्ध के बाद के युग में इसकी "गैर-पश्चिमी" और "वैकल्पिक" प्रकृति के कारण हुआ है, जिससे यह वैश्विक शक्ति संरचनाओं के भीतर दक्षिणी आवाजों के लिए एक मंच बन गया है। यह SSC के "राजनीतिक" पहलुओं को फिर से परिभाषित करने का आह्वान करता है, जो इसे केवल तकनीकी सहायता से परे देखता है और इसे दक्षिण के सामूहिक हित को आगे बढ़ाने वाले एक साधन के रूप में देखता है। DOI: 10.1080/14747731.2016.1265691

* "Rethinking South–South cooperation in the 2030 Agenda: towards a new research agenda" (Mawdsley, E., 2021) (tandfonline.com): मावड्सले (Mawdsley, 2021) का यह लेख 2030 एजेंडा के संदर्भ में दक्षिण-दक्षिण सहयोग (SSC) की पुनर्कल्पना पर केंद्रित है। लेखक SSC के बदलते स्वरूप को समझने के लिए एक नए शोध एजेंडे की आवश्यकता पर बल देते हैं, विशेष रूप से जब यह सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) से जुड़ा है। यह तर्क दिया जाता है कि SSC अब केवल दानदाताओं और प्राप्तकर्ताओं के बीच द्विध्रुवीय संबंध नहीं रहा है, बल्कि इसमें विविध प्रकार के अभिनेता (जैसे निजी क्षेत्र, नागरिक समाज) और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र शामिल हो गए हैं। मावड्सले SSC के राजनीतिक अर्थव्यवस्था आयामों की गहरी पड़ताल का आह्वान करते हैं, जिसमें शक्ति की गतिशीलता, हितों का टकराव, और वैश्विक विकास शासन पर इसके प्रभावों का विश्लेषण शामिल है। यह लेख SSC की पारदर्शिता, प्रभावशीलता, और जवाबदेही से संबंधित चुनौतियों को भी उजागर करता है, और सुझाव देता है कि भविष्य के शोध को इन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि SSC 2030 एजेंडा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक प्रभावी हो सके। DOI: 10.1080/01436597.2021.1948831

* "South-South and triangular cooperation" (ilo.org): अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का यह परिप्रेक्ष्य SSC को श्रम और रोजगार के क्षेत्र में देखता है। यह दर्शाता है कि कैसे SSC, विशेष रूप से त्रिकोणीय सहयोग (Triangular Cooperation - टीएससी) (दक्षिण-दक्षिण सहयोग को उत्तर के किसी देश या अंतर्राष्ट्रीय संगठन के समर्थन से विस्तारित करना), विकासशील देशों को सभ्य कार्य, सामाजिक सुरक्षा और श्रम मानकों को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। यह श्रम बाजारों में ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान पर केंद्रित है। ILO की रिपोर्ट और पहलें (initiative) त्रिकोणीय सहयोग के कई सफल उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जैसे कि बाल श्रम के उन्मूलन के लिए ब्राजील सरकार को दिए गए समर्थन को पेरू जैसे अन्य देशों के साथ साझा करना, जिसमें अमेरिका का श्रम विभाग (USDOL) वित्तीय सहायता प्रदान करता है और ILO तकनीकी सहायता और प्रशासनिक निरीक्षण प्रदान करता है। एक अन्य उदाहरण में, ब्राजील के राष्ट्रीय औद्योगिक शिक्षता सेवा (SENAI) और पेरू के व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (SENATI) के बीच जर्मन सहयोग एजेंसी (GIZ) के समर्थन से एक त्रिकोणीय सहयोग साझेदारी ने व्यावसायिक शिक्षा में ज्ञान और कौशल हस्तांतरण को बढ़ावा दिया है। यह श्रम बाजारों में ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान पर केंद्रित है।

* "What is 'South-South cooperation' and why does it matter? | UN DESA" (un.org) और "About South-South and Triangular Cooperation" (unsouthsouth.org): संयुक्त राष्ट्र (UN) के दस्तावेज़ SSC को एक प्रमुख विकास तंत्र के रूप में परिभाषित करते हैं। ये बताते हैं कि SSC समानता, राष्ट्रीय स्वामित्व और गैर-शर्तों के सिद्धांतों पर आधारित है।

यूएन साउथ-साउथ (UN South-South), विशेष रूप से, विभिन्न विकास चुनौतियों का सामना करने में SSC की प्रभावशीलता पर जोर देता है, जैसे कि गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, और जलवायु परिवर्तन। यह बताता है कि SSC कैसे अनुभवों और विशेषज्ञता के पारस्परिक आदान-प्रदान के माध्यम से दक्षिणी देशों को लाभान्वित करता है। UN DESA जैसे संगठन त्रिकोणीय सहयोग के माध्यम से विभिन्न विकास पहलों का समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए, चीन, घाना और UNDP के बीच नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर त्रिकोणीय सहयोग या मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका जल और आजीविका पहल (MENA Water and Livelihoods Initiative) त्रिकोणीय सहयोग के माध्यम से विकासशील देशों की चुनौतियों का समाधान करने के प्रभावी तरीके हैं। ये पहलें दर्शाती हैं कि कैसे एक पारंपरिक दाता या बहुपक्षीय संगठन (जैसे UNDP) दक्षिणी देशों (जैसे चीन और घाना) के बीच ज्ञान और संसाधनों के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बना सकता है, जिससे सभी भागीदारों को लाभ होता है और टिकाऊ विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति होती है।

* "South-South Cooperation Assistance Fund" (undp.org): संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) का यह संसाधन SSC के वित्तीय पहलुओं को उजागर करता है। यह दर्शाता है कि कैसे फंड और वित्तीय सहायता तंत्र SSC परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुगम बनाते हैं। यह उन तरीकों को इंगित करता है जिनसे दक्षिणी देश एक-दूसरे के विकास प्रयासों में योगदान करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटा सकते हैं।

* "जटिल विकास चुनौतियों से निपटने में, 'दक्षिण-दक्षिण सहयोग' का सहारा | यूएन समाचार" (news.un.org): यह समाचार रिपोर्ट SSC को जटिल वैश्विक चुनौतियों, जैसे कि महामारी प्रतिक्रिया, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, और खाद्य असुरक्षा, से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में प्रस्तुत करती है। यह वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को उजागर करती है जहां SSC ने मूर्त परिणाम दिए हैं, विकासशील देशों को उनकी विशिष्ट जरूरतों के अनुसार अनुकूलित समाधान प्रदान किए हैं।

* "दक्षिण-दक्षिण सहयोग" (chronicleindia.in): क्रॉनिकल इंडिया का यह लेख भारत के परिप्रेक्ष्य से SSC का एक सामान्य अवलोकन प्रदान करता है। यह भारत की बढ़ती भूमिका और SSC में उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, विशेष रूप से क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता के क्षेत्रों में।

* "मुद्दे एवं उभरती चुनौतियां" पर दक्षिणी प्रदाताओं - दक्षिणी दक्षिणी सहयोग के ..." (mea.gov.in): विदेश मंत्रालय (MEA) का यह दस्तावेज़ दक्षिणी देशों के प्रदाताओं के सामने आने वाले मुद्दों और चुनौतियों पर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह SSC की प्रभावशीलता बढ़ाने और नई वैश्विक वास्तविकताओं के अनुकूल होने के लिए सुधारों और नवाचारों की आवश्यकता पर जोर देता है।

* "India should reshape the framework of cooperation among developing countries: why is it needed" (orfonline.org/hindi): ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) का यह विश्लेषण भारत के लिए SSC के ढांचे को पुनर्गठित करने की आवश्यकता पर जोर देता है। यह तर्क देता है कि भारत को उभरती हुई वैश्विक गतिशीलता और दक्षिणी देशों की बदलती जरूरतों के जवाब में अपनी SSC रणनीतियों को अनुकूलित करना चाहिए, ताकि यह अधिक प्रभावी और प्रासंगिक बना रहे।

* "दक्षिण-दक्षिण सहयोग की अवधारणा एवं समकालीन दौर में भूमिका" (historyjournal.net): यह लेख SSC की अवधारणा का ऐतिहासिक विश्लेषण करता है और समकालीन वैश्विक व्यवस्था में इसकी भूमिका की पड़ताल करता है। यह

बताता है कि कैसे SSC ने विकासशील देशों के लिए एक सामूहिक आवाज और वैश्विक प्रशासन में अधिक प्रभावी भागीदारी का एक मंच प्रदान किया है।

ब्रिक्स (BRICS) के सदस्य देश, जो स्वयं दक्षिण-दक्षिण सहयोग के प्रमुख उदाहरण हैं, भी त्रिकोणीय सहयोग में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। उदाहरण के लिए, भारत और जापान ने अफ्रीकी देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए त्रिकोणीय सहयोग की पहल की है, जहां जापान वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है, जबकि भारत अपनी विशेषज्ञता और ज्ञान साझा करता है। इसी तरह, चीन की कुछ विकास परियोजनाएं भी तीसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी में त्रिकोणीय सहयोग मॉडल के तहत कार्यान्वित की जाती हैं। इस तरह, ब्रिक्स के सदस्य देश न केवल अपने समूह के भीतर, बल्कि एक व्यापक वैश्विक विकास ढांचे में भी योगदान करते हैं, जिससे SSC और TSC के बीच के संबंध को मजबूती मिलती है।

ये स्रोत सामूहिक रूप से दक्षिण-दक्षिण सहयोग के बहुआयामी स्वरूप को दर्शाते हैं - एक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी उपकरण जो विकासशील देशों को सामूहिक रूप से अपनी विकास आकांक्षाओं को प्राप्त करने में मदद करता है। यह साहित्य स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि SSC केवल एक सहायता तंत्र नहीं है, बल्कि यह एक सशक्तिकरण का साधन है जो दक्षिणी देशों को वैश्विक विकास एजेंडे को आकार देने में सक्षम करता है।

दक्षिण दक्षिण सहयोग अवधारणा एवं विकास का काल क्रम

दक्षिण-दक्षिण सहयोग (SSC) की जड़ें उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों के सामूहिक आत्मनिर्णय की भावना में निहित हैं। इसकी अवधारणा और विकास का काल क्रम निम्नलिखित प्रमुख चरणों में समझा जा सकता है:

* बांडुंग सम्मेलन (1955) और गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) (1961): SSC की वैचारिक नींव 1955 में बांडुंग, इंडोनेशिया में आयोजित अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन में रखी गई थी। इस सम्मेलन ने "बांडुंग के दस सिद्धांत" स्थापित किए, जिन्होंने संप्रभुता, समानता और आपसी गैर-हस्तक्षेप पर जोर दिया। इसके बाद, 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) की स्थापना हुई, जिसने नव स्वतंत्र देशों को शीत युद्ध की प्रतिद्वंद्विता से दूर रहने और अपनी साझा विकास चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक मंच प्रदान किया। यह अवधि दक्षिणी देशों के बीच राजनीतिक एकजुटता और सामूहिक आत्मनिर्भरता की भावना की शुरुआत थी।

* जी-77 का गठन (1964): विकासशील देशों के एक समूह के रूप में जी-77 (G-77) (अब 130 से अधिक सदस्यों के साथ) का गठन SSC के संस्थागतकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसका उद्देश्य विकासशील देशों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक सामूहिक आवाज प्रदान करना था। जी-77 ने दक्षिण-दक्षिण व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग के लिए मंच प्रदान किया।

* ब्यूंस आयर्स कार्य योजना (BAPA) (1978): तकनीकी सहयोग पर विकासशील देशों के बीच ब्यूंस आयर्स कार्य योजना (BAPA) को अक्सर आधुनिक SSC का जन्म प्रमाण पत्र माना जाता है। इसने SSC के सिद्धांतों और उद्देश्यों को औपचारिक रूप दिया, जिसमें अनुभवों, ज्ञान और कौशल के आदान-प्रदान के माध्यम से राष्ट्रीय और सामूहिक आत्मनिर्भरता को

बढ़ावा देना शामिल था। BAPA ने SSC को एक पारस्परिक, स्वैच्छिक और राष्ट्रीय स्वामित्व वाले तंत्र के रूप में रेखांकित किया।

* 21वीं सदी: पुनरुत्थान और विविधीकरण: 1990 के दशक में वैश्विक आर्थिक पुनर्गठन और उत्तर-दक्षिण सहायता पर बढ़ते फोकस के कारण SSC में थोड़ी गिरावट देखी गई। हालांकि, 21वीं सदी की शुरुआत के साथ, चीन, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं (ब्रिक्स (BRICS)) के उदय के साथ SSC ने एक महत्वपूर्ण पुनरुत्थान देखा। इन देशों ने न केवल आर्थिक विकास हासिल किया, बल्कि वे अन्य विकासशील देशों के लिए विकास मॉडल और सहायता प्रदाता के रूप में भी उभरे। इस चरण में SSC अधिक विविध हो गया, जिसमें केवल तकनीकी सहायता से परे व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचा विकास और ज्ञान साझाकरण शामिल था।

* सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (MDGs) और सतत विकास लक्ष्य (SDGs) के युग में SSC (2000 के बाद): सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (MDGs) (2000-2015) और बाद में एसडीजी (SDGs) (2015-2030) के आगमन ने वैश्विक विकास एजेंडे में SSC की भूमिका को और मजबूत किया। यह स्वीकार किया गया कि इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केवल पारंपरिक उत्तर-दक्षिण सहायता पर्याप्त नहीं होगी, और SSC एक आवश्यक पूरक बन गया। SSC ने दक्षिणी देशों को एसडीजी को स्थानीय संदर्भों के अनुसार अनुकूलित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए अभिनव समाधान खोजने में सहायक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

* नैरोबी घोषणा (2009) और ब्यूनस आयर्स एआरसी +40 सम्मेलन (2019): नैरोबी घोषणा ने वैश्विक विकास में SSC की बढ़ती भूमिका को पहचाना, जबकि BAPA +40 सम्मेलन ने SSC की उपलब्धियों को दोहराया और इसके भविष्य के लिए एक रोडमैप प्रदान किया। इसने SSC के दायरे को व्यापक बनाया, जिसमें त्रिकोणीय सहयोग और निजी क्षेत्र की भागीदारी शामिल थी।

आज, SSC एक गतिशील और विकसित अवधारणा है, जो विकासशील देशों के बीच बढ़ते आर्थिक एकीकरण, साझा चुनौतियों और वैश्विक प्रशासन में अधिक न्यायसंगत आवाज़ की आकांक्षा को दर्शाती है। यह सिर्फ एक सहायता मॉडल नहीं है, बल्कि एक साझेदारी का मॉडल है जो सामूहिक आत्मनिर्भरता और साझा समृद्धि की दिशा में काम करता है।

भारत और सतत विकास लक्ष्य

भारत, दुनिया की सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक और दक्षिण-दक्षिण सहयोग का एक प्रमुख पैरोकार, सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश ने 2030 एजेंडा को अपनी राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं में एकीकृत किया है और एसडीजी को स्थानीय बनाने तथा उन्हें हासिल करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

भारत की SDG प्राप्ति की दिशा में पहलें:

* नीति आयोग: भारत के नीति आयोग को देश में SDGs के राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय, निगरानी और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एसडीजी को बढ़ावा देने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग 'SDG इंडिया इंडेक्स' भी प्रकाशित करता है, जो राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करता है।

* प्रमुख योजनाएँ और कार्यक्रम: भारत सरकार ने विभिन्न प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों को SDGs के साथ संरेखित किया है:

* स्वच्छ भारत मिशन: SDG 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता) और SDG 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) को संबोधित करता है।

* प्रधान मंत्री जन धन योजना: SDG 1 (गरीबी नहीं) और SDG 10 (असमानता कम करना) को संबोधित करता है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर।

* आयुष्मान भारत योजना: SDG 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) को संबोधित करता है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करके।

* राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP): SDG 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है।

* उज्ज्वला योजना: SDG 7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा) को बढ़ावा देती है।

* जल जीवन मिशन: SDG 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता) के तहत हर घर में नल का पानी सुनिश्चित करता है।

* मेक इन इंडिया (Make in India) और स्टार्टअप इंडिया (Startup India): SDG 8 (समर्थ कार्य और आर्थिक विकास) और SDG 9 (उद्योग, नवाचार और अवसंरचना) को बढ़ावा देते हैं।

* डेटा और निगरानी: भारत ने एसडीजी संकेतकों की निगरानी और प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक मजबूत डेटा संग्रह और विश्लेषण प्रणाली विकसित की है।

* राज्यों की भूमिका: भारत में, राज्य एसडीजी के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि कई विकास पहल राज्य स्तर पर कार्यान्वित की जाती हैं।

चुनौतियाँ:

अपनी प्रगति के बावजूद, भारत को एसडीजी को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें बड़ी आबादी, क्षेत्रीय असमानताएं, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, और संसाधनों की कमी शामिल हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए न केवल घरेलू प्रयासों की आवश्यकता है, बल्कि मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विशेष रूप से दक्षिण-दक्षिण सहयोग, की भी आवश्यकता है।

सतत विकास लक्ष्य (SDG) एक दृष्टि में

संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा 2030 एजेंडा के तहत 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो सभी के लिए शांति और समृद्धि प्राप्त करने का एक वैश्विक खाका प्रदान करते हैं। ये लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं और एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं:

* कोई गरीबी नहीं (No Poverty): सभी जगह, हर रूप में गरीबी को समाप्त करना।

- * कोई भूख नहीं (Zero Hunger): भूख को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और बेहतर पोषण प्राप्त करना तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना।
- * अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण (Good Health and Well-being): सभी उम्र के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और कल्याण को बढ़ावा देना।
- * गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (Quality Education): समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना।
- * लैंगिक समानता (Gender Equality): लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना।
- * स्वच्छ जल और स्वच्छता (Clean Water and Sanitation): सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना।
- * सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा (Affordable and Clean Energy): सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- * सभ्य कार्य और आर्थिक विकास (Decent Work and Economic Growth): सभी के लिए स्थायी, समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सभ्य कार्य को बढ़ावा देना।
- * उद्योग, नवाचार और अवसंरचना (Industry, Innovation and Infrastructure): लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, समावेशी और टिकाऊ औद्योगीकरण को बढ़ावा देना और नवाचार को बढ़ावा देना।
- * असमानता कम करना (Reduced Inequalities): देशों के भीतर और देशों के बीच असमानता को कम करना।
- * टिकाऊ शहर और समुदाय (Sustainable Cities and Communities): शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना।
- * जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन (Responsible Consumption and Production): टिकाऊ उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना।
- * जलवायु कार्रवाई (Climate Action): जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना।
- * जल के नीचे जीवन (Life Below Water): महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और टिकाऊ उपयोग करना।
- * भूमि पर जीवन (Life On Land): स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों के टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देना, वनों का टिकाऊ प्रबंधन करना, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना, भूमि क्षरण को रोकना और पलटना तथा जैव विविधता के नुकसान को रोकना।

* शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं (Peace, Justice and Strong Institutions): सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना, सभी के लिए न्याय तक पहुंच प्रदान करना और सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना।

* लक्ष्यों के लिए भागीदारी (Partnerships for the Goals): कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना और सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना।

सतत विकास लक्ष्य प्राप्ति हेतु भारत के लिए अवसर:

दक्षिण-दक्षिण सहयोग (SSC) सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में भारत के लिए कई महत्वपूर्ण

दक्षिण-दक्षिण सहयोग (SSC) सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में भारत के लिए कई महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। भारत, एक प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्था और क्षमता निर्माण में एक अनुभवी देश के रूप में, SSC के माध्यम से न केवल अन्य दक्षिणी देशों की मदद कर सकता है, बल्कि अपने स्वयं के विकास लक्ष्यों को भी गति दे सकता है।

* ज्ञान और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान: भारत के पास विकास के विभिन्न क्षेत्रों में दशकों का अनुभव और विशेषज्ञता है, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य सेवा (जेनेरिक दवाएं), अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, और नवीकरणीय ऊर्जा। SSC के माध्यम से, भारत इन अनुभवों और "मेक इन इंडिया" जैसे मॉडलों को अन्य विकासशील देशों के साथ साझा कर सकता है, जिससे उन्हें अपने एसडीजी को प्राप्त करने में मदद मिलेगी (जैसे SDG 2: भूखमरी समाप्त करना, SDG 3: अच्छा स्वास्थ्य, SDG 9: उद्योग और नवाचार)। यह द्विपक्षीय आदान-प्रदान और बहुपक्षीय मंचों (जैसे आईबीएसए (IBSA), ब्रिक्स (BRICS)) के माध्यम से हो सकता है।

* क्षमताओं का निर्माण और संस्थागत सुदृढीकरण: भारत ने विभिन्न विकासशील देशों के हजारों पेशेवरों को प्रशिक्षण प्रदान किया है, विशेष रूप से भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम के तहत। यह क्षमता निर्माण SDG 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) और SDG 17 (लक्ष्यों के लिए भागीदारी) को बढ़ावा देता है। मजबूत संस्थागत ढाँचे और प्रशिक्षित कार्यबल SDG के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हैं।

* तकनीकी सहयोग और नवाचार का हस्तांतरण: भारत कम लागत वाली और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों के विकास में अग्रणी रहा है। SSC इन तकनीकों को अन्य दक्षिणी देशों तक पहुँचाने का एक मार्ग प्रदान करता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ महंगी पश्चिमी तकनीकों का उपयोग संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, भारत की सौर ऊर्जा पहल या डिजिटल भुगतान प्रणालियों का अन्य विकासशील देशों के साथ साझाकरण SDG 7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा) और SDG 9 (उद्योग, नवाचार और अवसंरचना) को बढ़ावा दे सकता है।

* साझा चुनौतियाँ, साझा समाधान: कई दक्षिणी देश समान विकास चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे कि गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट। SSC इन साझा चुनौतियों के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान और समाधान विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, सूखे से निपटने या जल प्रबंधन पर भारतीय अनुभव अफ्रीकी देशों के लिए प्रासंगिक हो सकता है, जिससे SDG 6 (स्वच्छ जल) और SDG 13 (जलवायु कार्रवाई) में मदद मिल सकती है।

* व्यापार और निवेश संबंध बढ़ाना: SSC केवल सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापार और निवेश को भी बढ़ावा देता है। भारत, अपने बढ़ते बाजार और विनिर्माण क्षमताओं के साथ, अन्य दक्षिणी देशों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार हो सकता है। दक्षिणी देशों के बीच बढ़ा हुआ व्यापार SDG 8 (समृद्धि और आर्थिक विकास) और SDG 17 (भागीदारी) को बढ़ावा देता है, आर्थिक विविधीकरण और क्षेत्रीय एकीकरण में योगदान देता है।

* जलवायु परिवर्तन पर सहयोग: भारत, एक विकासशील देश के रूप में, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशील है और उसने नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु अनुकूलन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। SSC के माध्यम से, भारत अन्य दक्षिणी देशों के साथ अपनी रणनीतियों और प्रौद्योगिकियों को साझा कर सकता है ताकि वे जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीले बन सकें, जिससे SDG 13 (जलवायु कार्रवाई) और SDG 15 (भूमि पर जीवन) को समर्थन मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे भारत SSC के माध्यम से वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को बढ़ावा दे रहा है।

* बहुपक्षीय मंचों में एकजुटता: SSC दक्षिणी देशों को संयुक्त राष्ट्र (UN) और अन्य बहुपक्षीय मंचों में एक सामूहिक आवाज़ उठाने का अवसर प्रदान करता है। भारत इस एकजुटता का नेतृत्व कर सकता है ताकि वैश्विक शासन संरचनाओं को अधिक समावेशी बनाया जा सके और विकासशील देशों की विशिष्ट जरूरतों और चिंताओं को बेहतर ढंग से संबोधित किया जा सके। यह SDG 17 (लक्ष्यों के लिए भागीदारी) के तहत वैश्विक भागीदारी को मजबूत करता है।

संक्षेप में, SSC भारत के लिए न केवल एक कूटनीतिक उपकरण है, बल्कि यह एसडीजी को प्राप्त करने के लिए एक व्यावहारिक और प्रभावी तंत्र भी है। साझा अनुभव, तकनीकी क्षमताएं और आपसी विश्वास इसे एक शक्तिशाली उपकरण बनाते हैं जो 2030 एजेंडा को वास्तविकता बनाने में मदद कर सकता है।

निष्कर्ष

दक्षिण-दक्षिण सहयोग (SSC) ने अपनी स्थापना के बाद से एक लंबा सफर तय किया है, जो उपनिवेशवाद विरोधी एकजुटता की भावना से विकसित होकर आज सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र बन गया है। कैसे ग्लोबल साउथ और SSC, पारंपरिक उत्तर-दक्षिण सहायता मॉडल के पूरक के रूप में, समानता, आपसी सम्मान और गैर-हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर आधारित एक प्रभावी और टिकाऊ विकास साझेदारी प्रदान करता है। SSC केवल तकनीकी या आर्थिक आदान-प्रदान नहीं है, बल्कि यह विकासशील देशों के बीच राजनीतिक सशक्तिकरण, ज्ञान साझाकरण और सामूहिक आत्मनिर्भरता का एक साधन भी है। संयुक्त राष्ट्र (UN) के दस्तावेज़ों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की रिपोर्टों और अकादमिक विश्लेषणों ने इसकी बहुआयामी प्रकृति और वैश्विक विकास एजेंडे में इसकी बढ़ती प्रासंगिकता को रेखांकित किया है। कैसे दक्षिणी देशों के बीच सहयोग को उत्तरी भागीदारों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन से और बढ़ाया जा सकता है, जिससे वे उनकी विशिष्ट विकास चुनौतियों का समाधान कर सकें। ब्रिक्स (BRICS) जैसे समूह, जो स्वयं दक्षिण-दक्षिण सहयोग के प्रमुख स्तंभ हैं, भी त्रिकोणीय सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत, एक प्रमुख दक्षिणी राष्ट्र के रूप में, SDGs को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता को दोहराता है और SSC में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। "अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन" (ISA) जैसी अंतर्राष्ट्रीय पहल तथा "मेक इन इंडिया", "स्वच्छ भारत मिशन" और "आयुष्मान भारत" जैसी राष्ट्रीय पहलों के माध्यम से, भारत न केवल अपने स्वयं के विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ा रहा है, बल्कि अन्य दक्षिणी देशों के लिए भी एक मॉडल और भागीदार के रूप में कार्य कर रहा है। ग्लोबल साउथ और दक्षिण-दक्षिण सहयोग 2030 एजेंडा की सफलता के लिए अपरिहार्य है। यह विकासशील देशों को सामूहिक रूप से अपनी चुनौतियों का सामना करने,

एक-दूसरे की सफलताओं से सीखने और एक अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ वैश्विक भविष्य का निर्माण करने में सक्षम बनाता है।

संदर्भ

- * United Nations. (n.d.). What is 'South-South cooperation' and why does it matter? | UN DESA. Retrieved from <https://www.un.org/development/desa/dspd/south-south-cooperation.html>
- * UN Office for South-South Cooperation. (n.d.). About South-South and Triangular Cooperation. Retrieved from <https://unsouthsouth.org/about-ssc-tsc/>
- * UNDP. (n.d.). South-South Cooperation Assistance Fund. Retrieved from <https://www.undp.org/south-south-cooperation-assistance-fund>
- * ILO. (n.d.). South-South and triangular cooperation. Retrieved from <https://www.ilo.org/global/how-we-work/south-south-and-triangular-cooperation/lang-en/index.htm>
- * Chronicle India. (n.d.). दक्षिण-दक्षिण सहयोग. Retrieved from <https://www.chronicleindia.in/south-south-cooperation>
- * MEA, Government of India. (n.d.). 'मुद्दे एवं उभरती चुनौतियाँ' पर दक्षिणी प्रदाताओं - दक्षिणी दक्षिणी सहयोग के Retrieved from https://www.mea.gov.in/articles-in-hindi.htm?dtl/24376/Southern_providers_on_issues_and_emerging_challenges__SouthSouth_Cooperation
- * ORF. (2022, November 28). India should reshape the framework of cooperation among developing countries: why is it needed. Retrieved from <https://www.orfonline.org/hindi/expert-speak/india-should-reshape-the-framework-of-cooperation-among-developing-countries-why-is-it-needed/>
- * History Journal. (n.d.). दक्षिण-दक्षिण सहयोग की अवधारणा एवं समकालीन दौर में भूमिका. Retrieved from <https://www.historyjournal.net/docs/30.pdf>
- * UN News. (2018, February 20). जटिल विकास चुनौतियों से निपटने में, 'दक्षिण-दक्षिण सहयोग' का सहारा. Retrieved from <https://news.un.org/hi/story/2018/02/1000671>
- * Bhan, M. (2017). Reclaiming the politics of South-South cooperation: Globalizations. *Globalizations*, 14(3), 329-346. DOI: 10.1080/14747731.2016.1265691
- * Mawdsley, E. (2021). Rethinking South-South cooperation in the 2030 Agenda: towards a new research agenda. *Third World Quarterly*, 42(9), 2099-2116. DOI: 10.1080/01436597.2021.1948831

संक्षिप्त शब्द सूची (List of Abbreviations)

- * BAPA: ब्यूनस आयर्स कार्य योजना (Buenos Aires Plan of Action)
- * BRICS: ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका (Brazil, Russia, India, China, South Africa)
- * DOI: डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर (Digital Object Identifier)
- * G-77: 77 देशों का समूह (Group of 77)

- * IBSA: भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका (India, Brazil, South Africa)
- * ILO: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization)
- * ISA: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance)
- * ITEC: भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (Indian Technical and Economic Cooperation)
- * MDGs: सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (Millennium Development Goals)
- * MEA: विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs)
- * NAM: गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement)
- * NEP: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy)
- * ORF: ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन (Observer Research Foundation)
- * SDGs: सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals)
- * SSC: दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South Cooperation)
- * TSC: त्रिकोणीय सहयोग (Triangular Cooperation)
- * UN: संयुक्त राष्ट्र (United Nations)
- * UNDP: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme)